

प्रेषक,

डी०एस० गर्बाल,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
चम्पावत।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: ०९ नवम्बर, 2016

विषय:- जनपद चम्पावत में जिला न्यायाधीश के आवासीय भवन निर्माण हेतु न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित कुल 0.319 है० भूमि की स्वीकृति को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-31/XVIII(II)/2015-18(01)/2015, दिनांक 23.04.2015 द्वारा जनपद, तहसील व ग्राम चम्पावत के खाता खतौनी संख्या-327 के खेत संख्या-5396 मध्ये 0.319 है० श्रेणी 9(3)ड. बंजर काबिल आबाद भूमि जिला न्यायाधीश के आवासीय भवन निर्माण हेतु न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके सन्दर्भ में न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा उक्त संगत शासनादेश को निरस्त करते हुए अन्य वैकल्पिक भूमि के हस्तान्तरण हेतु किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त वर्णित स्थिति के आलोक में संगत शासनादेश दिनांक 23.04.2015 को निरस्त करते हुए जनपद स्तर पर अन्य उपलब्ध वैकल्पिक भूमि न्याय विभाग को हस्तान्तरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 9.07.2015 के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से शासन को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डी०एस० गर्बाल)  
सचिव।

पू०प०सं०- 2285 /XVIII(II)/2016-18(01)/2015 तददिनांकित  
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(जे०पी० जोशी)  
अपर सचिव।